छत्तीसगढ़
सहकारी समाचार

वर्ष- 23 | अंक - 8 | जुलाई 2026 द्वितीय पाक्षिक | RNI NO. CHHHIN/2012/45105 | प्रकाशन तिथि 31 जुलाई | पृष्ठ-12 मूल्य 500/- वार्षिक

जामनगर के नए 'सहकार भवन' का लोकार्पण : अमित शाह ने सहकारिता को बताया ग्रामीण समृद्धि का आधार

जामनगर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के नवनिर्मित मुख्यालय 'सहकार भवन' का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा और गति दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन जामनगर और देवभूमि द्वारका के किसानों, सेवा सहकारी मंडलियों और दुग्ध सहकारी संस्थाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है नया भवन

अमित शाह ने बताया कि लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण रिजर्व बैंक और नाबार्ड के मानकों के अनुरूप किया गया है। 25 हजार वर्गफुट भूमि पर बने इस भवन में लगभग 47 हजार वर्गफुट का कार्यक्षेत्र है। इसमें प्रशिक्षण केंद्र, किसान छात्रावास, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, सम्मेलन कक्ष, सुरक्षित लॉकर सुविधा और भोजन की व्यवस्था जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भवन में 200 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है, जिससे इसे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है।

बैंक की उपलब्धियों का किया उल्लेख

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 1969 में ढाई लाख रुपए की पूंजी से शुरू हुआ जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक आज मजबूत वित्तीय संस्थान बन चुका है। उन्होंने बताया कि बैंक में 135 करोड़ रुपए की जमा राशि है, 780 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है और बैंक ने 24 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि बैंक का सकल एनपीए शून्य होना उसके कुशल प्रबंधन और सहकारी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

गांव-गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवाएं

अमित शाह ने कहा कि 40 शाखाओं के माध्यम से संचालित यह बैंक आने वाले समय में अपनी सेवाओं का और विस्तार करेगा। बैंक से 431 सेवा सहकारी मंडलियां, छह दुग्ध संघ और 652 दुग्ध उत्पादक मंडलियां जुड़ी हैं तथा यह लगभग डेढ़ लाख से अधिक

सहकारी सदस्यों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नया मुख्यालय किसानों और सहकारी संस्थाओं को अधिक आधुनिक और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

सहकारिता आंदोलन को मिली नई गति

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर देश के सहकारी आंदोलन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना, पैक्स में 20 से अधिक नए व्यवसाय शुरू करने, सहकारी संस्थाओं की ऑनलाइन ऑडिट व्यवस्था और विभिन्न सहकारी संस्थाओं को आपस में जोड़ने जैसी पहलें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी और किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगी।

जामनगर दौरे का भी किया जिक्र

अमित शाह ने कहा कि, भविष्य में जामनगर दौरे के दौरान वह सहकार भवन का अवलोकन करेंगे और सेवा सहकारी मंडलियों तथा दुग्ध मंडलियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहकारी क्षेत्र के विस्तार और किसानों की समृद्धि से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक आने वाले समय में और अधिक मजबूत होकर गांव-गांव तक किसानों, नागरिकों और सहकारी संस्थाओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संचालक मंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

प्रदेश में सहकारिता को मिलेगी नई मजबूती : जिला सहकारी संघों को राज्य सहकारी संघ से जोड़ने का निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संचालक मंडल की बैठक 22 जुलाई 2026 को संघ मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक में संघ के प्रशासनिक, वित्तीय, प्रकाशन, शिक्षा-प्रशिक्षण एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जिला सहकारी संघों को राज्य संघ से जोड़ने की पहल

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के सभी जिला सहकारी संघों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ की सदस्यता प्रदान करने का रहा। इस निर्णय से राज्य एवं जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं के बीच समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा। साथ ही सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता विकास तथा सहकारिता आंदोलन को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने में नई गति मिलेगी। यह निर्णय प्रदेश में सहकारिता के विस्तार और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी पहल माना जा रहा है।

2 सितम्बर को होगी 21वीं वार्षिक साधारण सभा

बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ की 21वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 2 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। साथ ही सदस्य संस्थाओं से बकाया अभिदाय एवं अंशदान की वसूली में तेजी लाने तथा सदस्य संस्थाओं से नियमित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

डिजिटल व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

संघ के प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार नवीन कंप्यूटर क्रय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शासन के निर्णयों के अनुरूप कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।

छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार को मिलेगा नया विस्तार

संचालक मंडल ने संघ द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार (पाक्षिक) के सदस्यता शुल्क में संशोधन करते हुए इसे रू 500 से बढ़ाकर रू2,000 प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया। साथ ही प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को पत्रिका का सदस्य बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि सहकारिता से जुड़ी गतिविधियों, योजनाओं एवं नवाचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके।

सहकारिता से समृद्ध कृषि की ओर : धमतरी ने छत्तीसगढ़ को दी नई पहचान

धमतरी बना प्रदेश का पहला जिला, जहाँ पैक्स के जरिए किसानों को मिलेगी ड्रोन स्प्रेयर सेवा

- सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खुद उड़ाया ड्रोन
- जिले की 10 समितियों में आधुनिक कृषि तकनीक का किया शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर करने की दिशा में धमतरी जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। धमतरी राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

10 चुनिंदा समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा का आधिकारिक शुभारंभ

वन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम लोहरसी स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जिले की 10 चुनिंदा समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री श्री कश्यप ने स्वयं ड्रोन उड़ाकर उसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और किसानों को खेती में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।

ड्रोन स्प्रेयर से उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव

कार्यक्रम में प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं ने ड्रोन स्प्रेयर का सफल प्रदर्शन किया। कृषि विशेषज्ञों और किसानों को दिखाया गया कि कैसे यह तकनीक कम समय में अधिक क्षेत्रफल में उर्वरकों और कीटनाशकों का बिल्कुल सटीक छिड़काव कर सकती है। इससे न केवल खेती की लागत घटेगी और श्रम की बचत होगी, बल्कि किसानों को रसायन के सीधे संपर्क से सुरक्षित भी रखा जा सकेगा।

धमतरी को कृषि नवाचारों का मॉडल जिला बनाया

इस अवसर मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि, मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। सहकारी समितियों के जरिए गाँव-गाँव तक ड्रोन पहुँचाना खेती को अधिक लाभकारी, सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाएगा। धमतरी को कृषि नवाचारों का मॉडल जिला बनाया जा रहा है और जल्द ही इस सुविधा का विस्तार राज्य की अन्य समितियों में भी किया जाएगा।

मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगी समितियाँ

यह पहल केवल कृषि तक सीमित नहीं है। CSC e-Governance Services India Limited के सहयोग से इन PACS को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इससे किसानों को खेती-किसानी के साथ-साथ विभिन्न डिजिटल और शासकीय सेवाएँ भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

पर्यावरण सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार

ड्रोन तकनीक से फसलों पर रसायनों का संतुलित और लक्षित उपयोग संभव होगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम पहुँचेगा और फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी। साथ ही, ड्रोन संचालन और रखरखाव से ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए द्वार खुलेंगे।

पौधरोपण और ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण

कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने समिति परिसर में नवनिर्मित कृषि एवं कीटनाशक विक्रय केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

इनकी भी रही मौजूदगी

इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ, डीएफओ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कोलकाता में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र

अमूल के संयंत्र का केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया भूमिपूजन, कहा- इससे सहकारिता को मिलेगी नई दिशा

नई दिल्ली/कोलकाता। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विजन के अनुरूप देश में सहकारिता के माध्यम से किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी पहल की जा रही है।

विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन केंद्र

उन्होंने बताया कि, परियोजना के प्रथम चरण में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे लगभग 1.20 लाख छोटे दुग्ध उत्पादकों एवं पशुपालकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। भविष्य में परियोजना की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण तक ले जाई जाएगी तथा यह संयंत्र विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन केंद्र होगा।

'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य में होगी बड़ी भूमिका

उन्होंने यह भी कहा कि, सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित 70 से अधिक किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पशुओं की नस्ल सुधार, आधुनिक डेयरी अवसंरचना, भंडारण सुविधाओं एवं सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि, यह परियोजना केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि देश में डेयरी सहकारिता, ग्रामीण रोजगार, मूल्य संवर्धन तथा सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सहकारिता किसानों को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम

श्री अमित शाह ने कहा कि, सहकारिता किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अमूल का उदाहरण देते हुए बताया कि उपभोक्ता द्वारा अमूल उत्पादों पर खर्च किए गए प्रत्येक 100 में से लगभग 87 रुपये सीधे किसानों एवं पशुपालकों के खातों में पहुँचते हैं। यही सहकारिता मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें उत्पादक को उसके श्रम का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है।

भाटागांव में मातृ शक्ति स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मनाया सहकारिता दिवस

■ सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन

रायपुर। सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 3 जुलाई को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक-61, भाटागांव की मातृ शक्ति स्व-सहायता समूह की बहनों द्वारा सहकारिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात सहकार गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व सहकार भारती की प्रांत महिला सहप्रमुख सुश्री पूजा पाण्डेय द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुश्री पाण्डेय ने कहा कि, महिलाएं सहकारिता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। सहकारिता का मूल भाव सामूहिक सहभागिता, परस्पर सहयोग और सामूहिक विकास पर आधारित है। जब महिलाएं सहकारिता से जुड़ती हैं, तो वे केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं करतीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सहकारिता का मूल उद्देश्य साथ मिलकर काम करना: उन्होंने कहा कि, सहकारिता का मूल उद्देश्य साथ मिलकर कार्य करना, आत्मनिर्भर बनना और सामूहिक विकास करना है। महिलाओं की सक्रिय सहभागिता इस उद्देश्य को साकार करने की सबसे बड़ी शक्ति है।

महिलाएं समाज और राष्ट्र स्तर पर निभाती हैं भूमिका

उन्होंने कहा कि, जब महिलाएं सहकारिता से जुड़ती हैं, तो उनकी भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे पूरे समाज और राष्ट्र के विकास की सहभागी बनती हैं। महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई गति मिलती है।

इनकी रही सहभागिता

कार्यक्रम में भाटागांव मातृ शक्ति स्व-सहायता समूह की बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीमती मंजू देवांगन, श्रीमती ममता यादव, श्रीमती मोना योगी, श्रीमती मोगरा वर्मा, श्रीमती किरण वर्मा, श्रीमती पार्वती देवांगन, श्रीमती चुन्नी साहू, श्रीमती देवकी साहू, श्रीमती गीता योगी, श्रीमती नूतन यादव, श्रीमती सरिता यादव, श्रीमती शुल्भा मोहरे सहित अन्य बहनों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सहकारिता से जुड़कर आत्मनिर्भरता, सामूहिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया।

वैज्ञानिक खेती ने बदली मिठाईलाल की तकदीर

रायपुर। बदलते कृषि परिदृश्य में आधुनिक तकनीकों को अपनाने वाले किसान नई सफलता की कहानियां लिख रहे हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम कछौड के प्रगतिशील किसान श्री मिठाईलाल पिता श्री इन्द्रदेव ने वैज्ञानिक खेती को अपनाकर यह साबित किया है कि नई सोच, सही मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीक खेती को अधिक लाभकारी बना सकती है। इफ्को नैनो डीएपी के सफल उपयोग से उन्होंने खेती की लागत घटाने के साथ बेहतर उत्पादन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। उनकी यह पहल अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गई है।

खेती से ही परिवार का भरण-पोषण करने वाले श्री मिठाईलाल पिछले कई वर्षों से कृषि कार्य से जुड़े हैं। बीते कुछ समय से रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमत और उत्पादन को लेकर बनी अनिश्चितता उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। इसी दौरान कृषि विभाग एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कछौड, शाखा मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से उन्हें इफ्को नैनो डीएपी की जानकारी मिली। विभागीय अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि यह आधुनिक उर्वरक कम मात्रा में उपयोग होने के बावजूद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराता है तथा फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है।

विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पर उन्होंने अपनी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग किया। कुछ ही समय बाद खेतों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे। फसल की बढ़वार पहले की तुलना में अधिक तेज हुई, पौधों की हरियाली बढ़ी और उनकी मजबूती भी स्पष्ट रूप से नजर आने लगी।

सहकारी बैंक दुर्ग के संचालक मंडल एवं ऋण उपसमिति की बैठक सम्पन्न : लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

दुर्ग। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन की अध्यक्षता में 30 जुलाई को बैंक के संचालक मंडल एवं ऋण उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बैंक संचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा एवं आवश्यक निर्णय लिए गए।

बैठक में श्री नरेश यदु, उपाध्यक्ष, श्री सुमन कुमार कोर्राम, सहायक संचालक कृषि, कु. शिवांगी महार, सहायक पंजीयक सहकारिता तथा श्री एस.के. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बैंक संचालन से संबंधित विषयों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं नाबार्ड (NABARD) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति तथा समिति प्रबंधकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पंजीयक सहकारिता को प्रस्ताव प्रेषित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

कृषकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृत : बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिलों की 30 सहकारी समितियों से संबद्ध कृषकों को विभिन्न कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए। वर्ष 2026-27 से 2028-29 की पूरक साख सीमा के अंतर्गत 1,505 किसानों को फसल ऋण हेतु कुल 15.36 करोड़ रुपये की साख सीमा स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त गन्ना उत्पादन हेतु 4 कृषकों को 13.50 लाख रुपये, कपास उत्पादन हेतु 4 कृषकों को 3.92 लाख रुपये तथा विभिन्न उद्यानिकी फसलों के लिए भी ऋण स्वीकृत किए गए।

योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

बैठक में अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन ने निर्देशित किया कि बैंक की ऋण नीति के अनुरूप कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सहकारी समितियों एवं कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक कृषक इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से जोड़ना सहकारी बैंक की प्राथमिकता है। बैठक में सुश्री कुसुम ठाकुर, अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक तथा श्री केके नायक, अधीक्षक सहित बैंक के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जशपुर जिले की सभी 44 सहकारी समितियां बनेंगी कॉमन सर्विस सेंटर

■ गांव में ही मिलेंगी 20 से अधिक डिजिटल सेवाएं

जशपुर। जशपुर जिले में ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जशपुर जिले की सभी 44 सहकारी समितियों को चरणबद्ध तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी, बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाओं के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

जिला पंचायत जशपुर के सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर संचालन एवं डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में रायपुर से आए राज्य परियोजना प्रबंधक सुरेन्द्र कुमार दास ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों, समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं कर्मचारियों को सीएससी संचालन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा लैम्प्स के माध्यम से सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।

इन सेवाओं का मिलेगा लाभ

प्रशिक्षण में बताया गया कि, सीएससी के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को आधार आधारित सेवाएं, बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं, डिजिटल भुगतान, किसान हितग्राही सेवाएं तथा विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं सहित 20 से अधिक डिजिटल सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

20 नई सहकारी समितियों का गठन

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि, पैक्स पुनर्गठन-2025 के बाद जशपुर जिले में 20 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राज्य शासन की प्राथमिकता इन समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे और ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सहजता से उपलब्ध हो सकेंगी।

बस्तर की दुग्ध सहकारिता को मिलेगी नई दिशा:अध्ययन भ्रमण पर गुजरात रवाना

■ आनंद और बनास डेयरी में सफल सहकारी मॉडल का करेंगे अध्ययन, आधुनिक डेयरी प्रबंध का मिलेगा प्रशिक्षण

रायपुर। बस्तर क्षेत्र में दुग्ध सहकारिता को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ (CGCDF) ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए लगभग 30 दुग्ध उत्पादक किसानों के अध्ययन भ्रमण दल को गुजरात के आनंद एवं बनासकांठा के लिए रवाना किया। किसानों को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र, आनंद में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस अध्ययन भ्रमण का मुख्य उद्देश्य किसानों को बनास डेयरी के सफल सहकारी मॉडल का प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना है। भ्रमण के दौरान किसान दुग्ध संकलन प्रणाली, सहकारी प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य संवर्धन, पशुपालक सेवाओं, विपणन व्यवस्था तथा आधुनिक डेयरी संचालन की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अध्ययन करेंगे।

अध्ययन भ्रमण दल को छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ के प्रबंध संचालक डॉ. एम. जयकृष्णा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महासंघ के उप प्रबंध संचालक सैकेत सामंता, प्रोजेक्ट हेड के. सी. बेहरा सहित महासंघ के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सभी अधिकारियों ने किसानों को सफल प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल बस्तर क्षेत्र में दुग्ध सहकारिता के विकास को नई गति प्रदान करेगी।

एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी से सीखेंगे आधुनिक डेयरी प्रबंधन

अध्ययन भ्रमण के दौरान किसान पालनपुर (गुजरात) स्थित बनास डेयरी (बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड) का भी भ्रमण करेंगे। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है तथा एशिया के सबसे बड़े दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन करती है। यह संस्था देश में सहकारिता आधारित डेयरी विकास का एक सफल एवं अनुकरणीय मॉडल मानी जाती है।

अवैध उर्वरक परिवहन पर सरकार की सख्ती

■ 3 मीट्रिक टन डीएपी खाद जब्त

रायपुर। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों के अवैध परिवहन, भंडारण और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेशभर में कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन किए जा रहे 3 मीट्रिक टन (60 बोरी) डीएपी खाद तथा एक पिकअप वाहन को जब्त किया है।

रघुनाथनगर में पकड़ी गई अवैध खाद : कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम रघुनाथनगर में की गई। जांच के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 टी 3538 में 60 बोरी डीएपी खाद परिवहन करते पाया गया। वाहन चालक अशोक कुमार से परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

खाद सहित पिकअप वाहन जब्त

दस्तावेजों के अभाव में उर्वरक के अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर पुलिस एवं कृषि विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खाद सहित पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी धीरेन्द्र तिवारी, उर्वरक निरीक्षक भूपेश गुप्ता, वरिष्ठ विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ) सहित कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे।

चार महीनों में 130 सफल ऑपरेशन, सुकमा जिला अस्पताल बना नई उम्मीद का केंद्र

रायपुर। सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जनहितैषी सोच और वन एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री अमित कुमार के प्रयासों से जिला अस्पताल सुकमा में तीन वर्षों से बंद पड़ा ऑर्थो (हड्डी रोग) ऑपरेशन थिएटर मार्च 2026 से दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद से अस्पताल में मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलना शुरू हुआ है।

जनवरी 2026 में एमएस ऑर्थो विशेषज्ञ डॉ. संदीप वर्मा की पदस्थापना के बाद अस्पताल में हड्डी रोग के उपचार और ऑपरेशन की सुविधा मजबूत हुई। पिछले चार महीनों में यहाँ 130 सफल ऑपरेशन किए गए हैं। इससे जिले के सैकड़ों मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिली है।

सोनमती और अनुराग की मुस्कान बनी बदलाव की पहचान

ग्राम कुकानार की 13 वर्षीय छात्रा कु. सोनमती पेड़ से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके दोनों पैरों की जाँघ की हड्डियाँ टूट गई थीं। जिला अस्पताल में समय पर उपचार, ब्लड बैंक से रक्त की उपलब्धता और सफल ऑपरेशन के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो रही है। इसी तरह, मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हुए कुम्हाररास निवासी चार वर्षीय अनुराग माड़वी का भी सफल ऑपरेशन किया गया। अब वह भी स्वस्थ है और सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।

अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता दूसरे शहर

पहले सुकमा के मरीजों को हड्डी रोग के इलाज के लिए जगदलपुर, रायपुर या ओडिशा के मलकानगिरी जाना पड़ता था। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था और इलाज में देरी भी होती थी। अब जिला अस्पताल में ही निःशुल्क ऑपरेशन, दवाइयाँ, भोजन और भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं।

ओडिशा से भी आ रहे हैं मरीज

सुकमा जिला अस्पताल की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का असर अब पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र तक दिखाई दे रहा है। वहाँ के मरीज भी हड्डी रोग के उपचार के लिए सुकमा आ रहे हैं। यह अस्पताल की बढ़ती विश्वसनीयता का प्रमाण है।

अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने का संकल्प

कलेक्टर श्री अमित कुमार ने कहा कि जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और आधुनिक संसाधनों के कारण जिला अस्पताल की सेवाएँ लगातार बेहतर हो रही हैं। सोनमती और अनुराग जैसे बच्चों की मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सुकमा जिला अस्पताल आज क्षेत्र के लोगों के लिए नई उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन चुका है।

ऑयल पाम की खेती से बदली किसानों की तकदीर

गरियाबंद। छुरा विकासखंड के ग्राम कसहीबाहरा (बेहरामाड़ा) निवासी श्री रामबरन वर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम योजना के माध्यम से खेती, किसानी में नई पहल की है। उन्होंने वर्ष 2025-26 में नेचर कृषि फार्म समूह का गठन कर ऑयल पाम की आधुनिक खेती अपनाई। श्री वर्मा के पास लगभग 20 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। वे पहले धान के साथ अन्य फसलें उगाई जाती थीं। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से ऑयल पाम योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बोर खनन, फेंसिंग, ड्रिप सिंचाई तथा रख-रखाव अनुदान जैसी सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने ड्रिप सिंचाई तकनीक के साथ ऑयल पाम का रोपण किया और अंतरवर्ती फसलों के रूप में आम, शहतूत एवं सब्जियों की खेती शुरू की। इससे भूमि का बेहतर उपयोग हुआ साथ ही उन्हें अधिक मुनाफा होने लगा।

वर्तमान में उनके द्वारा समूह बनाकर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में ऑयल पाम का रोपण किया जा चुका है। इसे देखते हुए आसपास के किसान भी प्रेरित होकर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। समूह के माध्यम से लगाए गए ऑयल पाम के रोपण जिले

तिरिथ राम साहू बना रहे गांव को प्लास्टिक मुक्त

■ 85 की उम्र में भी स्वच्छता का जज्बा बरकरार

रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने में उम्र कोई बाधा नहीं है। विकासखंड कवर्धा की ग्राम पंचायत धरमपुरा के 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक श्री तिरिथ राम साहू इसका जीवंत उदाहरण हैं। जीवन के इस पड़ाव में भी वे पूरे उत्साह और समर्पण के साथ गांव को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। पिछले छह माह से श्री साहू प्रतिदिन सुबह गांव की गलियों की सफाई, प्लास्टिक कचरा संग्रहण तथा नालियों की सफाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही वे ग्रामीणों को खुले में कचरा नहीं फेंकने, गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। श्री तिरिथ राम साहू घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। कचरा संग्रहण के दौरान स्वच्छाग्रही दीदियों के साथ ग्रामीणों को सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं तथा गांव में एकत्रित प्लास्टिक कचरे को संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने में भी सक्रिय रहते हैं। स्वयं हमेशा कपड़े का थैला उपयोग कर वे दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की पहल : मुफ्त बीज के साथ दिया गया तकनीकी मार्गदर्शन

■ मछली पालकों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही प्रदेश सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित स्पॉन संवर्धन योजना के तहत प्रदेश में आदिवासी मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी एवं प्रतापपुर के चार अनुसूचित जनजाति वर्ग के मत्स्य कृषकों को निःशुल्क गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज (स्पॉन) एवं नर्सरी जाल वितरित किए गए।

हितग्राहियों को दिया गया नर्सरी जाल

मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बसदेई में तैयार उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन को सुरक्षित ऑक्सीजन पैकिंग के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचाया गया, जिससे परिवहन के दौरान मत्स्य बीज की गुणवत्ता और जीवित रहने की क्षमता बनी रहे। स्पॉन के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रत्येक हितग्राही को नर्सरी जाल भी उपलब्ध कराया गया।

दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण: इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने हितग्राहियों को तालाब की वैज्ञानिक तैयारी, स्पॉन संचयन, नर्सरी प्रबंधन, जल गुणवत्ता संरक्षण तथा आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया। इससे मत्स्य कृषकों को कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

स्वरोजगार की दिशा में बड़ी पहल

मत्स्य पालन विभाग का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के मत्स्य कृषकों को गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज, आवश्यक संसाधन एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना तथा राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। विभाग की यह पहल ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्य पालन को स्वरोजगार और आजीविका के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सहकारिता से आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़ के किसान

भारत सरकार ने सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए वर्ष 2021 में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश के हर ग्राम पंचायत तक सहकारी समितियों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सहकारिता से लाभ मिल सके। सहकारिता के माध्यम से एक बेहतर और समृद्ध ग्रामीणों का निर्माण करना है।

छत्तीसगढ़ में सहकारिता का प्रसार

छत्तीसगढ में 6063 सहकारी समितियाँ कार्यरत: छत्तीसगढ राज्य में कुल 11,650 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ (पैक्स), 1,949 दुग्ध, 1,002 मत्स्य और 1,054 लघु वनोपज सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं।

760 नई समितियाँ गठित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर अब तक छत्तीसगढ़ में 310 मत्स्य, 297 दुग्ध और 153 लघु वनोपज समितियाँ नई गठित की जा चुकी हैं।

सहकारिता के माध्यम से रोजगार और सशक्तिकरण

राज्य गठन के समय केवल 1,333 सहकारी समितियाँ सक्रिय थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। किसानों को ऋण, बीज, खाद, कीटनाशक और विपणन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो रही है। राज्य में 515 नई प्राथमिक कृषि साख समितियाँ भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के कुल सदस्य अब 30.26 लाख हैं, जिनमें से 19.38 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं।

राज्य में सहकारी केंद्रीय बैंक की 345 शाखाएँ संचालित

कृषि ऋण और वित्तीय सुदृढ़ता: राज्य में 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हैं, जिनकी 345 शाखाएँ संचालित हो रही हैं। इनमें से 262 शाखाएँ कम्प्यूटरीकृत हैं। राज्य के 2058 पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

किसानों के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त आसान कृषि ऋण की सुविधा

राज्य सरकार और नाबार्ड के सहयोग से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 5 लाख रुपए तक का कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा है। पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु उद्योगों के लिए भी 1त्न से 3त्न ब्याज दर पर ऋण सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक 15.56 लाख किसानों को 6,936 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरित किया जा चुका है।

डिजिटलीकरण और पारदर्शिता

राज्य में सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण का कार्य वर्ष 2022-23 से आरंभ हुआ। अब तक 2,028 समितियाँ ई-पैक्स मोड में परिवर्तित की जा चुकी हैं। डिजिटलीकरण से किसानों के खाते, ऋण विवरण और ब्याज गणना पारदर्शी और रियल टाइम हो गए हैं।

धान खरीद और किसानों को लाभ

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 25 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके लिए 34,349 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री किसान उन्नति योजना के तहत 11,928.59 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। कुल 46276 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किया गया।

स्व-सहायता समूह की दीदियां बना रही हैं प्राकृतिक राखियां, रक्षाबंधन पर बढ़ेगी आय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आड़ावाल, जगदलपुर द्वारा रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल से महिलाओं को कौशल विकास के साथ-साथ त्योहारी सीजन में अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी मिल रहा है।

30 दीदियों को मिला प्राकृतिक राखी निर्माण का प्रशिक्षण: जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 21 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सातों जनपदों से आई स्व-सहायता समूह की 30 दीदियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आकर्षक, हस्तनिर्मित और पर्यावरण अनुकूल राखियां बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

स्थानीय संसाधनों से तैयार हो रही हैं आकर्षक राखियां : प्रशिक्षण में महिलाओं ने धान, चावल, लालभाजी के बीज, कुकुम्बर (खीरा) के बीज, मयूर पंख, बांस तथा अन्य प्राकृतिक एवं सजावटी सामग्रियों से सुंदर और कलात्मक राखियां बनाना सीखा। प्रशिक्षकों ने उन्हें डिजाइन चयन, रंग संयोजन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग तथा बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की बारीकियों की भी जानकारी दी।

त्योहारी सीजन में बढ़ेगी आय, अन्य महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी प्रतिभागी अपने-अपने जनपदों में लौटकर स्व-सहायता समूह की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर राखियों का निर्माण करेंगी। इससे स्थानीय बाजार में हस्तनिर्मित एवं प्राकृतिक राखियों की उपलब्धता बढ़ेगी और समूह की महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।

पर्यावरण संरक्षण के साथ बस्तर की कला को भी मिल रही पहचान

प्राकृतिक सामग्री से तैयार की जा रही ये राखियां पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती हैं। स्थानीय संसाधनों के उपयोग से तैयार इन उत्पादों के माध्यम से बस्तर की पारंपरिक कला, स्थानीय शिल्प और ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मकता को नई पहचान मिल रही है। यह पहल 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को भी सशक्त कर रही है।

महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए सहकारिता की भावना आवश्यक

■ **छिंदबहार में महिला सहकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन**

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संभागीय कार्यालय जगदलपुर की प्रशिक्षण इकाई द्वारा आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत एक दिवसीय महिला सहकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ग्राम छिंदबहार के आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया।

प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं एवं ग्रामीण महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सहकारिता का अर्थ, महत्व एवं सिद्धांत, सहकारी समितियों के गठन एवं पंजीयन की प्रक्रिया तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

आपसी सहयोग से सशक्त बन सकती हैं महिलाएं

प्रशिक्षण में बताया गया कि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आपसी सहयोग और एकजुटता के माध्यम से सहकारी समितियों का गठन कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों एवं स्थानीय संभावनाओं की पहचान कर उन्हें सामूहिक गतिविधियों से जोड़ने से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। सहकारिता की भावना के साथ गठित समितियां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ गांव, गरीब एवं किसानों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सहकारी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प : प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सहकारिता को समूह के सफल संचालन एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि, सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिल सकती है। महिलाओं ने ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए तथा सहकारी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सक्रिय सहभागिता का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध सहकारी समिति सहित विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के गठन, कार्यप्रणाली एवं लाभ के संबंध में भी जानकारी दी गई। महिलाओं ने अपने क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सहकारी समिति गठित करने में रुचि व्यक्त की।

आत्मनिर्भर बनना सहकारिता की मूल भावना : प्रशिक्षण वर्ग में महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि साथ मिलकर कार्य करना, सामूहिक प्रयासों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनना ही सहकारिता की मूल भावना है।÷ महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से सहकारिता आंदोलन को ग्रामीण स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

संसाधनों की कमी नहीं रोक सकी किसान पुत्र रमन की उड़ान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी अंचल से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी कभी भी बड़े सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम उदरसई निवासी किसान पुत्र रमन कुमार ने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फस्टडी के दम पर वर्ष 2026 की नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

एक साधारण कृषक परिवार से आने वाले रमन ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कुसमी में अध्ययन करते हुए कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। उनकी इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कलेक्टोरेट में उन्हें सम्मानित कर उपहार भेंट किया तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

रमन के माता-पिता खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कक्षा 6वीं से ही एकलव्य विद्यालय में अध्ययन करते हुए नियमित मेहनत की। उन्होंने किसी भी निजी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि नियमित अध्ययन, अनुशासित दिनचर्या और आत्मविश्वास को अपनी सफलता का आधार बनाया।

रमन के पिता श्री राजेश कुमार ने बताया कि उनके गांव से नीट परीक्षा में सफल होने वाले रमन पहले छात्र हैं। बेटे की उपलब्धि से पूरे गांव में उत्साह और गर्व का माहौल है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय रमन की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया।

सम्मान समारोह के दौरान रमन ने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता के लिए महंगी कोचिंग नहीं, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य, सही रणनीति, नियमित अध्ययन और स्वयं पर विश्वास सबसे अधिक जरूरी है। उन्होंने युवाओं से समय का सदुपयोग करने, कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने और पूरी लगन के साथ अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया।

रमन कुमार की यह सफलता केवल एक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में छिपी प्रतिभाओं की क्षमता का सशक्त प्रमाण है। उनकी कहानी आज प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को यह विश्वास दिला रही है कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर सपना संभव है।

मंगनार गांव में महिलाओं को दिया गया सहकारी प्रशिक्षण

■ स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने बड़ी संख्या में लिया भाग

जगदलपुर। आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के अंतर्गत संभागीय कार्यालय जगदलपुर की प्रशिक्षण इकाई ने दरभा विकासखंड के ग्राम मंगनार में महिलाओं के लिए सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में प्रशिक्षण का आयोजन हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जय मां दुर्गा स्व-सहायता समूह, जय मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह एवं निर्जला स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों सहित ग्राम की बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

महिलाओं से सक्रिय भागीदारी का आह्वान

प्रशिक्षण वर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के वरिष्ठ प्रशिक्षक विवेक पांडे ने महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत एवं सहकारी आंदोलन की मूल अवधारणाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी देते हुए महिलाओं से सहकारी समितियों के गठन एवं संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

विभिन्न पहलुओं की दी गई जानकारी

उन्होंने विभिन्न प्रेरक एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि, सहकारिता के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, स्वरोजगार के नए अवसर विकसित कर सकती हैं। सामूहिक प्रयासों से अपने परिवार, गांव की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिला समूहों को सहकारिता के माध्यम से बचत, उद्यमिता, सामूहिक विपणन एवं आजीविका संवर्धन के विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी दी गई।

इनकी रही बड़ी भूमिका: कार्यक्रम को सफल बनाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती बसंती मौर्य, सहायिका श्रीमती पार्वती नाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संपर्क साधक श्री रोमांचल पाणिग्राही का सहयोग सराहनीय रहा।

जाति प्रमाण पत्र मिलने से खुला शिक्षा और रोजगार का रास्ता

रायपुर। शासन की महत्वकांक्षी पहल सेवा सेतु से जरूरतमंदों को प्रमाण पत्र बनाने की राह आसान कर दी है। दुर्ग निवासी सुश्री हिरामन पिता स्वर्गीय राम बगस आर्थिक रूप से साधारण परिवार से हैं। सुश्री हिरामन को आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। लंबे समय से प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पिता की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था।

इसी दौरान उन्हें सेवा सेतु के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन के बाद सेवा सेतु प्रबंधक ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर आवेदन की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और समन्वय किया। संबंधित विभाग द्वारा आवेदन का परीक्षण कर 30 जून 2026 को उनका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अनुमोदित कर जारी कर दिया गया।

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद सुश्री हिरामन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहती है कि अब उन्हें आवश्यक दस्तावेज बनवाने तथा भविष्य में अपने परिवार के शैक्षणिक एवं अन्य सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब स्वयं के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपने भाई-बहनों का भी जाति प्रमाण पत्र बना पाउंगी। उन्होंने सेवा सेतु की त्वरित, पारदर्शी और जनहितैषी कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

स्पॉन संवर्धन योजना बनी आजीविका का सशक्त आधार-23 लाख मछली बीज प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हरिश्चंद्र जांगड़े

धमतरी। ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित शासन की स्पॉन संवर्धन योजना जिले के मत्स्य पालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में 27 जुलाई 2026 को शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, सांकरा में ग्राम पंचायत चरमुडिया के हितग्राही श्री हरिश्चंद्र जांगड़े को योजना के अंतर्गत 23 लाख स्पॉन (जीरा आकार के मछली बीज) का वितरण किया गया। यह सहायता उनके मत्स्य पालन व्यवसाय को नई दिशा देने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मत्स्य पालन में बढ़ती संभावनाएँ और लाभ

श्री हरिश्चंद्र जांगड़े लंबे समय से मत्स्य पालन से जुड़े हैं। उनका मानना है कि यदि समय पर गुणवत्तायुक्त मछली बीज उपलब्ध हो जाए तो उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। पहले उन्हें निजी स्रोतों से महंगे दाम पर बीज खरीदना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी और कई बार गुणवत्तापूर्ण बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। शासन की स्पॉन संवर्धन योजना के माध्यम से अब उन्हें प्रमाणित एवं स्वस्थ मछली बीज सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

वैज्ञानिक संवर्धन से उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद

23 लाख स्पॉन को वैज्ञानिक पद्धति से संवर्धित कर आगे फिंगरलिंग एवं मत्स्य बीज के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त मछली बीज की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि आसपास के मत्स्य पालकों को भी समय पर बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। परिणामस्वरूप जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज (स्पॉन) संवर्धन कर मत्स्य बीज विक्रय से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को मत्स्य बीज (स्पॉन) संवर्धन,तालाब सुधार एवं इनपुट्स मत्स्य बीज (स्पॉन) आदि हेतु रुपए 30000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

सखी वन स्टॉप सेंटर बना सहारा, अवसाद से जूझ रही महिला को मिला नया जीवन

रायपुर। जीवन में अपनों को खोने का दुख किसी भी व्यक्ति को गहरे मानसिक आघात में डाल सकता है। ऐसे समय में यदि भावनात्मक और सामाजिक सहारा मिल जाए, तो जीवन को नई दिशा मिल सकती है। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर ने ऐसी ही एक महिला को अवसाद और नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर उसे फिर से सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया।

दंतेवाड़ा के आवंराभाटा क्षेत्र की रहने वाली प्रीति सिंह ने कुछ वर्ष पहले अपने पुत्र को बीमारी के कारण खो दिया था। इससे पहले उनके पति का भी निधन हो चुका था। लगातार मिले इन दुखद आघातों के कारण वह गहरे अवसाद में चली गई और धीरे-धीरे शराब की आदी हो गई। उन्होंने घर पर रहना छोड़ दिया और कई दिनों तक बिना भोजन के इधर-उधर भटकती रहीं।

सूचना मिलते ही सखी सेंटर ने की मदद

स्थानीय लोगों ने महिला की स्थिति की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी। इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम मौके पर पहुंची। महिला की मानसिक और नशे की स्थिति को देखते हुए 112 पुलिस सेवा की सहायता से उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और उन्हें सखी सेंटर लाया गया। सेंटर में उनकी नियमित देखभाल की गई। चिकित्सकों की निगरानी में उपचार कराया गया और लगातार काउंसलिंग के माध्यम से उनका मानसिक संबल बढ़ाया गया।

काउंसलिंग से बढ़ा आत्मविश्वास

काउंसलिंग के दौरान प्रीति सिंह ने बताया कि वह दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थीं, लेकिन पति और पुत्र के निधन के बाद अकेलापन और तनाव उन्हें नशे की ओर ले गया। सखी सेंटर के काउंसलरों ने उन्हें स्वास्थ्य सुधार और सुरक्षित वातावरण में रहने की सलाह दी। हालांकि उन्होंने नारी निकेतन में रहने के बजाय अपनी बेटी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की।

बेटी से मिलाया, परिवार से जोड़ा

सखी सेंटर की टीम ने महिला की बेटी का पता लगाया और उसे अपनी मां की देखभाल के लिए प्रेरित किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में सखी सेंटर की टीम ने प्रीति सिंह को पूरी तरह स्वस्थ और नशा मुक्त होने के बाद सुरक्षित रूप से रायपुर में उनकी बेटी के पास पहुंचाया। अपनी बेटी के साथ सुरक्षित पहुंचने के बाद प्रीति सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग और सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

महिलाओं के लिए भरोसे का केंद्र

यह कहानी दर्शाती है कि सखी वन स्टॉप सेंटर केवल संकट में फंसी महिलाओं को आश्रय ही नहीं देता, बल्कि उन्हें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान कर जीवन की नई शुरुआत करने में भी मदद करता है। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल महिलाओं के संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी और संवेदनशील प्रयास है।

मुंडागांव लैम्पस में प्रबंधकारिणी के लिए सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में बस्तर जिले के ग्राम मुंडागांव स्थित लैम्पस भवन में प्रबंधकारिणी वर्ग के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा ÷सहकार से समृद्धि÷ की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने बताया कि, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस अवसर पर मछली पालन, बकरी पालन, व्यवसाय विकास तथा अन्य आयवर्धक गतिविधियों के संबंध में भी उपयोगी जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं एवं सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर एवं आय में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया गया।

किसानों ने भी साझा किए अनुभव

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रबंधकारिणी सदस्यों एवं कृषकों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव साझा किए तथा सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग विशेष रूप से सराहनीय रहा।

आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना : चिंगपाल लैम्पस में दिया गया प्रशिक्षण

■ **गांव, गरीब और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण**

चिंगपाल (बस्तर)। बस्तर जिले के दरभा विकासखंड स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चिंगपाल (लैम्प्स) में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के अंतर्गत संभागीय कार्यालय जगदलपुर की प्रशिक्षण इकाई ने यह आयोजन रखा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे ने ग्रामीण कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत एवं उद्देश्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने

कहा कि गांव, गरीब और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा

उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि ÷स्वस्थ मृदा, स्वस्थ मानव÷ की अवधारणा को अपनाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर किसानों से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को धीरे-धीरे कम करते हुए जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया गया। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया कि जैविक खेती से भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

ऋण लेने की प्रक्रिया समझाई गई

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को लैम्प्स संस्था द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सुविधा, कृषि निवेश, गोपालन, बकरी पालन एवं अन्य आयवर्धक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही लैम्प्स द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

सहकारी संस्थाओं की योजनाओं का लाभ उठाएं

कार्यक्रम को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चिंगपाल के प्राधिकृत श्री काढ़ी राम नाग ने भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से सहकारी संस्थाओं की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने तथा जैविक खेती को अपनाकर अपनी आय एवं जीवन स्तर में सुधार लाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण में उपस्थित किसानों ने इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अत्यंत उपयोगी एवं समय की आवश्यकता बताते हुए भविष्य में भी नियमित आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में लैम्प्स चिंगपाल के कर्मचारी श्री अमितेश सेठिया, श्री ईश्वर बघेल एवं श्री दिनेश कुमार का सहयोग सराहनीय रहा।

छोटे अलनार में महिलाओं को दिया सहकारी प्रशिक्षण

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम छोटे अलनार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के प्रशिक्षक श्री मितेश पानीग्राही द्वारा सहकारिता के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, उद्भव एवं विकास, सदस्यता, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, नियमित बैठकों का महत्व, बैंक लिंकिंग, सहकारी संस्था का पंजीयन, व्यवसाय विकास तथा सहकार से समृद्धि जैसे विषयों पर व्यावहारिक एवं उपयोगी मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संपर्क साधक श्री करूंगाकर मंडन का विशेष सहयोग सराहनीय रहा।

भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए संबल बनी शासन की योजनाएं, राम सिंह के जीवन में आई आर्थिक मजबूती

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड निवासी श्री राम सिंह का परिवार इसका सजीव उदाहरण है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और महतारी वंदन योजना से मिल रही नियमित आर्थिक सहायता ने उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

श्री राम सिंह ने बताया कि वे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। स्वयं की कृषि भूमि नहीं होने के कारण पहले परिवार का खर्च चलाना कठिन था। राज्य शासन की दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उन्हें प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। यह राशि परिवार की आवश्यक जरूरतों को

पूरा करने और विपरीत परिस्थितियों में सहारा देने का काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है। इस नियमित आर्थिक सहयोग से घरेलू खर्च, दैनिक आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने में सुविधा मिल रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ हुई है।

श्री राम सिंह ने बताया कि उनके परिवार में चार बच्चे हैं, जो समय-समय पर मजदूरी कर परिवार का सहयोग करते हैं। शासन की योजनाओं से मिलने वाली सहायता ने परिवार के जीवन-यापन को आसान बनाया है और जरूरत के समय आर्थिक सुरक्षा का आधार भी दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाएं भूमिहीन और श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। श्री राम सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की संवेदनशील पहल से उनके जैसे हजारों परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर और भविष्य के प्रति नया विश्वास मिला है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए राष्ट्रीय सम्मान का अवसर

रायपुर। दिव्यांगजनों के अधिकारों, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2026) के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले नवाचारों, उत्कृष्ट सेवाओं और प्रेरणादायी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना तथा समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित करना है।

जनदर्शन: कलेक्टर ने दो हितग्राहियों को मौके पर ही प्रदान किया श्रवण यंत्र

मुंगेली। जिला कलेक्टोरेट में आज जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जनदर्शन में पहुंचे दो श्रवण बाधित हितग्राहियों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें मौके पर ही श्रवण यंत्र प्रदान कर लाभान्वित किया। ग्राम खपरीडीह निवासी श्रीमती सहोदरा साहू ने बताया कि उन्हें लंबे समय से सुनने में कठिनाई हो रही थी। जिला चिकित्सालय में जांच कराने पर चिकित्सकों ने श्रवण यंत्र लगाने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे इसे खरीदने में असमर्थ थीं। उनकी समस्या सुनते ही कलेक्टर ने तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर मौके पर ही श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया। इसी प्रकार विनोबा भावे वार्ड, मुंगेली निवासी श्री मनहरण श्रीवास ने भी श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने का आवेदन

प्रस्तुत किया। कलेक्टर के निर्देश पर उन्हें भी तत्काल श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। अचानक मिली इस सहायता से दोनों हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनदर्शन के माध्यम से उनकी वर्षों की समस्या का त्वरित समाधान हुआ है।

'सहकारिता से समृद्धि' विषय पर किसानों को दिया गया प्रशिक्षण संपन्न

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में 18 जुलाई को आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के अंतर्गत बस्तर जिले के ग्राम पंचायत भडीस में किसानों के लिए सहकारिता से समृद्धि विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा ने किसानों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, लाभ एवं सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार के नए अवसरों का सृजन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक प्रयासों द्वारा कृषि, पशुपालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।

सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने की सलाह: कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव रमेश बघेल ने भी किसानों को संबोधित करते हुए शासन द्वारा संचालित विभिन्न पंचायत स्तरीय योजनाओं की जानकारी दी। ग्राम विकास एवं जनकल्याण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने ग्रामीणों से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं एवं सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया।

किसानों को उपयोगी लगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में उपस्थित किसानों ने सहकारिता के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त कर उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री सुदन राम मौर्य का विशेष योगदान सराहनीय रहा।

सहकारी सप्ताह पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

मोहला। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित "सहकारी सप्ताह" के दौरान सहकारिता विषय पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीएम श्री गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मोहला में सहकारिता विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, राजनांदगांव के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया गया।

चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त किए भाव

प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सहकारिता की भावना, सामूहिक विकास, आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण समृद्धि जैसे विषयों को अपने निबंधों एवं चित्रों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सहकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों एवं सामाजिक महत्व के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा उनमें सहयोग, सहभागिता एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना था।

सहकारिता के आदर्शों को जीवन में अपनाने की सीख

इस अवसर पर सहकारिता विभाग, मोहला से श्री मनोज तारम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहित विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सहकारिता के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के साथ हुआ तथा सहकारी सप्ताह के माध्यम से विद्यार्थियों में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य को सफल बताया गया।

नैनो उर्वरकों पर बढ़ रहा किसानों का भरोसा

खेती बन रही लाभकारी मिल रहे बेहतर परिणाम

■ **कम लागत, लाने ले जाने, उपयोग में आसानी और बेहतर उत्पादन ने जीता किसानों का मन**

रायपुर। आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचार आधारित उर्वरकों के उपयोग से प्रदेश के किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफ्को) द्वारा विकसित नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी किसानों के लिए प्रभावी, किफायती और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभर रहे हैं। इन उर्वरकों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आने के साथ-साथ उत्पादन और पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में भी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

महिला किसान ने अपने अनुभव बताए : सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम सोनपुर खुर्द की प्रगतिशील किसान श्रीमती भगवती राजवाड़े ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग से मिले अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि, उनके परिवार के पास लगभग 1.23 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जहां पिछले वर्ष धान सहित अन्य फसलों में नैनो उर्वरकों का उपयोग किया गया। इससे फसलों की वृद्धि बेहतर हुई और उत्पादन में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिला।

आसान परिवहन भी नैनो उर्वरकों का बड़ा लाभ : श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि नैनो उर्वरकों का सबसे बड़ा लाभ उनका आसान परिवहन और उपयोग है। पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियों की तुलना में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी की छोटी बोतलों को खेत तक ले जाना सरल है, जिससे समय, श्रम और परिवहन लागत में कमी आती है। उन्होंने बताया कि निर्धारित मात्रा में पानी के साथ घोल बनाकर इसका छिड़काव आसानी से किया जा सकता है, जिससे पोषक तत्व समान रूप से फसलों तक पहुंचते हैं।

नैनो उर्वरक मिट्टी की सेहत का रखते हैं ध्यान

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नैनो उर्वरक पौधों तक पोषक तत्वों की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, जिससे उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ती है तथा खेती की लागत कम करने में मदद मिलती है। साथ ही संतुलित उपयोग से मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को नैनो उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग के संबंध में लगातार प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का करें उपयोग : भगवती राजवाड़े

श्रीमती भगवती राजवाड़े ने किसानों से अपील की कि, वे आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का अधिकाधिक उपयोग करें। उनका कहना है कि, इससे कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के साथ खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के प्रयास प्रदेश में कृषि विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

मछली पालन से आत्मनिर्भर बनीं मदनूबाई सालाना 2 लाख रुपये से अधिक की आय

रायपुर। मछलीपालन (मत्स्य पालन) ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए आर्थिक मजबूती, स्वरोजगार और सतत आजीविका का एक बेहतरीन जरिया बनकर उभर रहा है। कम लागत और सीमित जमीन में शुरू किया जाने वाला यह व्यवसाय परिवारों को तेजी से आत्मनिर्भर बना रहा है ।

राज्य शासन की मत्स्य पालन विभाग की योजनाएं ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीजापुर जिले की श्रीमती मदनूबाई तलाण्डी इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। विभाग की योजना का लाभ लेकर उन्होंने मछलीपालन को अपनी आजीविका बनाया और आज वे हर वर्ष 2 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।

60 प्रतिशत अनुदान से मिला नया अवसर

श्रीमती मदनूबाई तलाण्डी ने अपनी 1 हेक्टेयर निजी भूमि पर मत्स्य पालन विभाग की योजना के तहत 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर तालाब का निर्माण कराया। तालाब बनने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से मछलीपालन शुरू किया, जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि होने लगी।

प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग बना सफलता की कुंजी

मत्स्य पालन विभाग द्वारा समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सलाह उपलब्ध कराई गई। इससे मछली उत्पादन बढ़ा और उनका व्यवसाय निरंतर विस्तार करता गया। आज मछलीपालन उनके परिवार की आय का प्रमुख स्रोत बन चुका है।

आर्थिक रूप से सशक्त हुआ परिवार

मछलीपालन से होने वाली नियमित आय ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। अब उनका परिवार आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है और बच्चों की शिक्षा सहित दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रहा है।

कृत्रिम गर्भाधान से बदली पशुपालक की तस्वीर, बढ़ा दुग्ध उत्पादन

सूरजपुर। विकासखंड रामानुजनगर के ग्राम अगस्तपुर निवासी श्री हीरालाल सोनवानी ने पशुपालन विभाग की योजनाओं एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा का लाभ लेकर अपने पशुपालन व्यवसाय को नई दिशा दी है। पिछले लगभग 16 वर्षों से पशुपालन से जुड़े श्री सोनवानी आज क्षेत्र के सफल पशुपालकों में शामिल हैं।

वर्तमान में उनके पास 04 दुधारू गाय, 03 बछिया एवं 04 बछड़े हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के कृष्णपुर उपकेंद्र से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उन्हें उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप उनके डेयरी व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में वे प्रतिदिन लगभग 35 से 40 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में भी निरंतर बढ़ोतरी हुई है।

श्री हीरालाल सोनवानी ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से बेहतर नस्ल के पशु मिलने के कारण दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। उन्होंने अन्य पशुपालकों से भी विभाग की इस सुविधा का लाभ उठाकर उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करने की अपील की।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पशुपालन विभाग द्वारा संचालित मादा-वत्स पालन योजना के अंतर्गत एक बछिया भी प्रदान की गई थी, जिससे उनके पशुधन में वृद्धि हुई और व्यवसाय को मजबूती मिली।

श्री हीरालाल सोनवानी ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं समय-समय पर उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सेवाओं के लिए शासन और पशुपालन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के सहयोग से उनका पशुपालन व्यवसाय अधिक लाभकारी और आत्मनिर्भर बन सका है।

छोटे आमाबाल में सदस्य किसानों को दिया दो दिन का सहकारी प्रशिक्षण

जगदलपुर। बस्तर जिले के ग्राम छोटे आमाबाल के पंचायत भवन में 17-18 जुलाई को सदस्य कृषक भाइयों के लिए द्वि-दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के प्रशिक्षक श्री मितेश पानीग्राही द्वारा सहकारिता के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, उद्भव एवं विकास, सहकारी ढांचा, सदस्यता, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, नियमित बैठकों का महत्व, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के दायित्व, प्रबंधक के कार्य, लैम्प्स (LAMPS) के कार्य, आमसभा की भूमिका तथा ऋण नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

सहकारिता अपनाने से आएगा जीवनस्तर में सुधार: प्रशिक्षण के दौरान "सहकार से समृद्धि" की अवधारणा पर विशेष बल देते हुए बताया गया कि, सहकारिता को अपनाकर ग्रामीण किसान अपनी आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। इस अवसर पर मछली पालन, बकरी पालन, गौ-पालन तथा अन्य व्यवसाय विकास गतिविधियों के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के संबंध में भी व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं एवं योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

किसानों ने दिखाई सक्रियता

प्रशिक्षण में उपस्थित सदस्य कृषकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई तथा सहकारिता आधारित आजीविका, सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

बिरींगपाल में किसानों को दिया गया सहकारी प्रशिक्षण

■ राज्य सहकारी संघ का आयोजन, इनकम बढ़ाने के बताए गए उपाय

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के ग्राम पंचायत बिरींगपाल में 23 जुलाई को किसानों के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा ने किसानों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत एवं सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (लैम्प्स) के उद्देश्य, सहकारी ऋण नीति तथा किसानों की आय में वृद्धि के विभिन्न उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर हरित क्रांति को गति देने तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

सरपंच का किसानों से आग्रह, उठाएं लाभः कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच श्री धरमदास नाग ने पंचायत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। वहीं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुकदेव नाग ने पंचायत विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया।

किसानों को दी गई उपयोगी जानकारी

प्रशिक्षण में उपस्थित किसानों ने सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण समृद्धि के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त की तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के श्री सुदन राम मौर्य का विशेष योगदान सराहनीय रहा।

महिलाओं का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण संपन्न

जगदलपुर। बस्तर जिले के ग्राम बड़े अलनार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में यह आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के प्रशिक्षक श्री मितेश पानीग्राही द्वारा सहकारिता के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, उद्भव एवं विकास, सदस्यता, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, नियमित बैठकों का महत्व तथा ÷सहकार से समृद्धि÷ की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला।

स्वरोजगार के बताए गए उपायः इसके साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन के विभिन्न उपायों से अवगत कराते हुए मछली पालन, बकरी पालन, गौ-पालन तथा व्यवसाय विकास के संबंध में व्यवहारिक एवं उपयोगी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता, आय में वृद्धि तथा ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया।

नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक रावत पहुंचे महासमुंद जिले के दौरे पर

रायपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उप प्रबंध निदेशक श्री गोवर्धन सिंह रावत ने गुरुवार को महासमुंद जिले का दौरा किया। उनके साथ नाबार्ड छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय से मुख्य महाप्रबंधक श्री डी.के. गवली, महाप्रबंधक श्री शीतांशु शेखर, उप महाप्रबंधक श्री ब्रजेन्द्र किशोर सामंतराय, उप महाप्रबंधक श्री अजय थुटे तथा जिला विकास प्रबंधक, महासमुंद श्री प्रियव्रत साहू भी उपस्थित रहे।

भोरिंग में नवगठित पैक्स पहुंचे, कम्प्यूटरीकरण के दिए निर्देश : दौरे के प्रारंभ में श्री रावत ने ग्राम भोरिंग स्थित नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) पहुंचकर समिति के व्यवसाय संचालन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि तुमगांव पैक्स से इस नवगठित समिति के पृथक्करण की प्रक्रिया सुगमतापूर्वक सम्पन्न की जाए। उन्होंने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी), रायपुर को निर्देशित किया कि समिति के कम्प्यूटरीकरण कार्य में समुचित सहयोग प्रदान किया जाए तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।

सिरपुर में ऋण वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल : इसके पश्चात श्री रावत सिरपुर पहुंचे, यहां छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व पर बल दिया तथा स्वीकृत ऋणों का वितरण किया। जिसमें ड्रोन, कंबाइन हार्वेस्टर, केसीसी एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ऋण की वित्तीय सहायता शामिल थी। श्री रावत ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की सिरपुर स्थित नवीन शाखा भवन का लोकार्पण भी किया।

रायतुम पैक्स का किया भ्रमण, उपलब्धियों को सराहा

तत्पश्चात श्री रावत ने रायतुम पैक्स का भ्रमण किया, जो पैक्स कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए किसानों के ऋण संबंधी विवरणों की वास्तविक समय में प्रविष्टि कर रही है। उन्होंने समिति की इस उपलब्धि की सराहना की तथा पैक्स कर्मचारियों से कम्प्यूटरीकरण में आ रही कठिनाइयों एवं विभिन्न गतिविधियों से जुड़े एकाधिक पोर्टलों को सरल बनाए जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया। दोनों पैक्स परिसरों में श्री रावत ने पौधरोपण भी किया। इस दौरान डीसीसीबी रायपुर से श्री चंद्राकर एवं श्री अविनाश शर्मा उपस्थित रहे।

वनोपज सहकारी समिति गीदम ने रचा इतिहास : 38 वर्षों में सबसे अधिक कीमत पर बिका तेंदूपत्ता

■ 10 हजार 909 रुपये प्रति मानक बोरा तक मिली कीमत, करीब 4 हजार संग्राहक परिवारों को मिलेगा बोनस का लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की गीदम प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति ने तेंदूपत्ता विक्रय में 38 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। 16 जुलाई 2026 को आयोजित ऑनलाइन निविदा में गीदम समिति के तेंदूपत्ते को 10,909 प्रति मानक बोरा तक का ऐतिहासिक मूल्य प्राप्त हुआ है। दंतेवाड़ा जिले की प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति गीदम ने तेंदूपत्ता विक्रय में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन निविदा में समिति का तेंदूपत्ता 10 हजार 609 रुपये और 10 हजार 909 रुपये प्रति मानक बोरा की रिकॉर्ड दर पर बिका। यह गीदम समिति के 38 वर्षों के इतिहास में तेंदूपत्ता विक्रय की सबसे अधिक कीमत है।

38 वर्षों में सबसे अधिक कीमत पर बिका तेंदूपत्ता

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे वनाश्रित परिवारों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया और गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली का लाभ अब सीधे तेंदूपत्ता संग्रहकों तक पहुंच रहा है।

करीब 4 हजार संग्राहक परिवारों को मिलेगा बोनस का लाभ

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि तेंदूपत्ता रिकॉर्ड दर पर बिकने से समिति को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसका लाभ बोनस के रूप में समिति से जुड़े करीब 4 हजार तेंदूपत्ता संग्रहक परिवारों को मिलेगा। इससे वनाश्रित परिवारों की आय बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

डिजिटल व्यवस्था से भुगतान में पारदर्शिता

राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण, बोनस, छात्रवृत्ति, बीमा और अन्य लघु वनोपज योजनाओं में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संग्रहकों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा की जा रही है। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध हुई है।

जशपुर में खाद-बीज का पर्याप्त भंडार : किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

■ सहकारी समितियों में 5,056 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध

रायपुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए जशपुर जिले की सभी सहकारी समितियों में रासायनिक उर्वरकों एवं प्रमाणित बीजों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शासन द्वारा निर्धारित दरों पर अपने निकटतम सहकारी समिति से ही खाद एवं बीज प्राप्त करें।

उप संचालक कृषि श्री एम.आर. भगत ने बताया कि, जिले में वर्तमान में कुल 5,056.740 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। इसमें 2,283.140 मीट्रिक टन यूरिया, 1,401.050 मीट्रिक टन डीएपी, 524.540 मीट्रिक टन एनपीके, 467.500 मीट्रिक टन सुपर फॉस्फेट तथा 380.510 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफपोटाश का पर्याप्त भंडार शामिल है।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी उपलब्ध : संतुलित एवं आधुनिक उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों में 5,124 बोतल नैनो यूरिया तथा 6,421 बोतल नैनो डीएपी, कुल 11,545 बोतलें भी किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में प्रमाणित बीजों का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में 1,454 क्विंटल धान, 88 क्विंटल अरहर, 457.64 क्विंटल उड़द, 10 क्विंटल मूंगफली, 8.14 क्विंटल रामतिल तथा 0.72 क्विंटल तिल का प्रमाणित बीज सहकारी समितियों एवं कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

जरूरत के मुताबिक खाद लें किसान

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि, जिले में खाद एवं बीज की किसी प्रकार की कमी नहीं है और किसानों की आवश्यकता के अनुरूप सभी आवश्यक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। विभाग ने किसानों से आवश्यकता के अनुसार ही खाद एवं बीज का उठाव करने, शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खरीदारी करने तथा अनावश्यक भंडारण एवं भ्रामक अफवाहों से बचने की अपील की है। विभाग ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि खरीफ फसलों की बुवाई सुचारु रूप से हो और कृषि उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भारत में को-ऑपरेटिव सेक्टर की प्रमुख चुनौतियां

एक प्रमुख संघर्ष उस स्थिति में मौजूद है जहाँ सहकारी समितियों का पंजीयक (राज्य प्राधिकारी) समामेलन, प्रशासन और परिसमापन का प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग लाइसेंस और पूंजी पर्याप्तता जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों को नियंत्रित करता है। इससे अधिकार क्षेत्र के विवाद, असंगत पर्यवेक्षण और नियामक अंतर उत्पन्न होते हैं।

शासन संबंधी कमियां

विभिन्न सहकारी समितियों में पारदर्शिता और वास्तविक लोकतांत्रिक प्रथा की कमी के कारण अभिजात वर्ग का नियंत्रण, खराब जवाबदेही और सदस्यों के आवागमन को कम होता है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का पतन सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से जुड़ा था।

वित्तीय बाधाएँ और अविकसित अवसंरचना

कई संस्थान पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिससे नुकसान को कम करने, आर्थिक तनाव का सामना करने या विस्तार को निधि देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और बाज़ार संबंधों की गंभीर कमी कृषि और ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं

पूर्व-मौजूद सामाजिक पदानुक्रम, जाति-आधारित विभाजन और संरचनात्मक असमानताएँ सहकारी समितियों के भीतर समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जो उनके समावेशी आदर्शों के विपरीत है।

तीव्र बाज़ार की प्रतिस्पर्धा

सहकारी समितियाँ वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और फिनटेक कंपनियों के खिलाफग्राहकों को बनाए रखने के लिये संघर्ष करती हैं, जो अधिक परिष्कृत उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

परिचालनात्मक और तकनीकी बाधाएं

एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल विभाजन मौजूद है, जहाँ कई ग्रामीण सहकारी समितियों के पास आधुनिक डिजिटल अकाउंटिंग, ERP सिस्टम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खराब फिजिकल कनेक्टिविटी और कमज़ोर रसद सहकारी नेटवर्क की दक्षता और भौगोलिक विस्तार को सीमित करती हैं।

सहकारी समितियां कैसे होंगी मज़बूत

भारत देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहकारिता को मजबूत बनाने की दिशा में निम्न कदम उठाए जा सकते हैं।

तकनीकी एकीकरण

मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन खाता खोलना और डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करें ताकि टेक-प्रेमी सदस्यों को आकर्षित किया जा सके और संचालन की दक्षता बढ़ाई जा सके। सामान्य ऋण सॉफ्टवेयर, डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम और ई-कॉमर्स एकीकरण (जैसे– ONDC और GeM प्लेटफॉर्म) लागू करना ताकि संचालन सरल हो और बाज़ार में पहुँच का विस्तार हो सके।

वित्तीय गहनता

सहकारी वित्तीय संस्थाओं को मूलभूत बचत/ऋण से आगे बढ़कर निवेश उत्पाद, बीमा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करने चाहिये, ताकि सदस्य समग्र वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। सदस्य स्वस्थ्य को क्रेडिट फ्लो बेहतर बनाने के लिये को-ऑपरेटिव्स को MUDRA, CGTMSE और NABARD जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं से औपचारिक रूप से जोड़ा जाए।

संस्थागत सशक्तीकरण

सहकारी संस्थाओं के लिये संगठित प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएँ, और क्लीयर कैरियर पाथवे लागू किये जाएँ ताकि पेशेवर प्रबंधकों की एक मज़बूत टीम तैयार की जा सके।

मूल्य श्रृंखला विकास

गोदाम, शीत भंडारण और सामान्य सुविधा केंद्र जैसी अवसंरचना में सार्वजनिक तथा सहकारी निवेश को प्राथमिकता दी जाए, ताकि व्यर्थता कम हो एवं बाज़ार तक पहुँच बेहतर हो सके। इसके अलावा सदस्य-स्वामित्व वाली लॉजिस्टिक सहकारी संस्थाएँ स्थापित करने से सप्लाई चेन लागत कम होगी व दक्षता बढ़ेगी।

ब्रांडिंग और विविधीकरण

प्रीमियम कीमतें प्राप्त करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रमाणन के साथ मज़बूत 'अंब्रेला ब्रांड' (जैसे– "CoopMade" या 'भारत ऑर्गेनिक्स') विकसित एवं प्रचारित करना। ईको-टूरिज़्म, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक कृषि (जैसे- हाइड्रोपोनिक्स) व डिजिटल सेवाओं में सहकारी मॉडलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ताकि उन्हें नवाचार केंद्रों के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके।

भारत में सहकारिताओं की वर्तमान स्थिति

अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बाद देश में सहकारिता के क्षेत्र में कितनी तेजी से विकास हुआ है, पढ़िए उसकी एक बानगी।

व्यापक विस्तार और व्यापक पहुंच : भारत में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं, जो 30 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 32 करोड़ सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करती हैं तथा देश के लगभग 98त्न ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती हैं। लगभग 10 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सहकारिताओं से जुड़ी हुई हैं, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास में इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

नए क्षेत्रों में रणनीतिक विस्तार : 32,000 से अधिक नई बहु-उद्देशीय दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण पारंपरिक ऋण से आगे बढ़कर सहकारी क्षेत्र के विस्तार हेतु किये जा रहे सशक्त प्रयासों को दर्शाता है। यह विस्तार राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं, जैसे- नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना के माध्यम से रणनीतिक रूप से सुदृढ़ किया गया है, ताकि भारतीय सहकारिताओं को उच्च-मूल्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से एकीकृत किया जा सके।

सुदृढ़ वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन

नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) द्वारा वार्षिक ?95,000 करोड़ से अधिक का वितरण किया जा रहा है, जो सहकारी क्षेत्र के विस्तार हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराता है। नीतिगत फोकस को नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना तथा सहकारिताओं को विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना जैसे बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

सामाजिक सहभागिता की अनूठी पहल बच्चों को मिला पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन

- 324 स्कूलों में 16 हजार बच्चों के लिए हुआ 'न्योता भोज' महाअभियान
- कहीं खीर-पूड़ी, कहीं पनीर की सब्जी, तो कहीं हरी सब्जियों के साथ परोसा गया विशेष भोजन

रायपुर। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों (बालवाटिका से कक्षा 8 तक) के बच्चों को सभी स्कूली दिनों में गर्म, ताजा और पौष्टिक पका हुआ भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों की मदद करके उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करना है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण) के तहत बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड में सामाजिक सहभागिता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। शिक्षा विभाग की पहल पर विकासखंड के 324 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक साथ 'न्योता भोज महाअभियान' आयोजित किया गया। इस अभियान में लगभग 16 हजार विद्यार्थियों को स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसा गया।

बच्चों के पोषण और नियमित उपस्थिति पर जोर: कलेक्टर श्री विश्वदीप एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में आयोजित इस महाअभियान का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना है। 'न्योता भोज' के माध्यम से समाज की सहभागिता को विद्यालयों और बच्चों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

स्थानीय संसाधनों से तैयार किए गए विविध व्यंजन

अभियान के दौरान विद्यालयों में बच्चों के लिए अलग-अलग प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। कहीं खीर-पूड़ी और पनीर की सब्जी परोसी गई, तो कहीं हरी सब्जियों, गर्म भोजन और मिष्ठान के साथ बच्चों को विशेष भोजन कराया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और सब्जियों का उपयोग करते हुए भोजन तैयार किया गया। बच्चों ने उत्साह और खुशी के साथ सामूहिक भोज का आनंद लिया। इस महाअभियान को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रह्लाद जैन, बीआरसी श्री डी. राय, संकुल प्राचार्यों, संकुल समन्वयकों, प्रधान अध्यापकों और मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अन्य विकासखंडों में भी होगा विस्तार

जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश पांडे ने बताया कि 'न्योता भोज' का उद्देश्य बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना और विद्यालयों में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन इस अभियान को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ सफल बना रहे हैं। भैरमगढ़ में आयोजित यह सामूहिक 'न्योता भोज' महाअभियान बच्चों के पोषण, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। इस सफलता के बाद जिले के अन्य विकासखंडों में भी चरणबद्ध तरीके से ऐसे सामूहिक न्योता भोज आयोजित किए जाएंगे।

महज 80 दिन में पक जाती है मक्के की यह किस्म

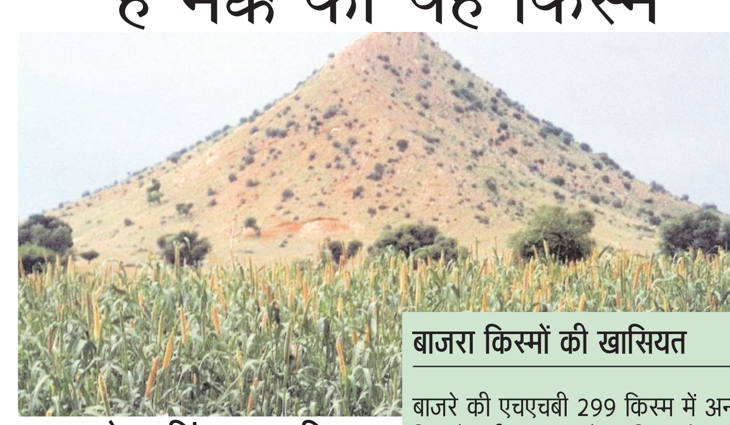

- 19 से 20 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक देती है उपज
- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किया विकसित

नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की उन्नत हाइब्रिड किस्में तैयार की हैं। इन बाजरा किस्मों में एचएचबी-299 और एचएचबी-67 संशोधित-2 शामिल हैं। इन उन्नत किस्मों के बीज अब हरियाणा से निकलकर दूसरे राज्यों में बिकेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसके लिए बीज कंपनियों से समझौते किए हैं।

दूसरे राज्यों को भी देने की तैयारी

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में तैयार बाजरे की ये किस्में हरियाणा के साथ-साथ देश के अनेक राज्यों में किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि उसका मकसद बाजरे के क्वालिटी वाले बीज किसानों तक समय पर उपलब्ध कराकर कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाना है। प्राइवेट बीज कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग से इन किस्मों का अधिक से अधिक प्रसार संभव होगा, जिससे बड़ी तादाद में किसान लाभान्वित होंगे।

बाजरा किस्मों की खासियत

बाजरे की एचएचबी 299 किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार मिलती है और यह रोगरोधी भी है. यह बाजरा की अधिक आयरन से भरपूर (73 पी.पी.एम.) हाइब्रिड किस्म है. इसके सिट्टे शंक्वाकार और मध्यम लंबे होते हैं। एचएचबी 299 किस्म 80-82 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अच्छा रख रखाव करने पर यह किस्म 49.0 मन प्रति एकड़ यानी लगभग 20 क्विंटल तक पैदावार देने की क्षमता रखती है. यह किस्म जोगिया रोगरोधी है।

एचएचबी 67-2 किस्म

बाजरे की यह उन्नत किस्म पहले वाली किस्म एचएचबी 67 संशोधित का जोगिया रोग प्रतिरोधी वैरायटी है. यह हाइब्रिड किस्म हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बारानी क्षेत्रों में आम खेती के लिए 2021 में सिफ़ारिश की गई थी. एचएचबी-67 संशोधित के नर जनक एच 77/833-2-202 को जोगिया रोग प्रतिरोधी बनाया गया है. इस नई विकसित संकर किस्म एचएचबी-67 संशोधित-2 में एचएचबी 67 संशोधित के सभी गुण जैसे बहुत जल्द पकना, सूखे का कम असर, दाने और चारे की अच्छी क्वालिटी, अगेती, मध्यम और पछेती बुवाई के लिए उपयुक्त आदि शामिल हैं.

जिला पंचायतों के सीईओ की समीक्षा बैठक : गांवों के विकास से ही विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा साकार : सीएम साय

■ **मुख्यमंत्री विष्णुदेप साय ने कहा- अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, यही सुशासन की कसौटी**

रायपुर। ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। यदि ग्राम पंचायतें सशक्त हों, गांव आत्मनिर्भर बनें और प्रत्येक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का सहभागी बने, तभी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प वास्तविक रूप ले सकेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित एसआईआरडी परिसर, निमोरा में आयोजित प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही।

प्रदेशवासियों को बिना भेदभाव मिले लाभ

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि, सुशासन का वास्तविक अर्थ यही है कि शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्राम पंचायतें जनभागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाने का सबसे प्रभावी मंच हैं। अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए ग्रामीणों का विश्वास जीतना होगा।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : सीएम

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि, शासकीय योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और गांव का प्रत्येक नागरिक स्वयं विकास यात्रा का सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां जनभागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रभावी योजना के माध्यम से आदर्श विकास मॉडल विकसित किए जा सकें।

जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि, 1 जुलाई से लागू विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना का निर्माण प्राथमिकता से किया जाए। इसके माध्यम से जल संरक्षण, कृषि, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग ही स्थायी विकास का आधार है। उन्होंने प्रत्येक जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जल संरक्षण की कार्ययोजना तैयार करने तथा वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

अब लक्ष्य करोड़पति दीदी बनाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब सरकार उन्हें उद्यमिता, कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़कर बड़ी संख्या में करोड़पति दीदी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें स्व-सहायता समूहों, कौशल विकास, आजीविका गतिविधियों और नई औद्योगिक नीति से उत्पन्न अवसरों से जोड़ा जाए।

बस्तर के अंतिम गांव तक पहुंचे विकास की रोशनी

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर संभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों तक कभी पहुंचना कठिन था, वहां अब सड़क, बिजली, आवास, राशन, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। सरकार का लक्ष्य विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

छत्तीसगढ़ में खेती का बदलता ट्रेंड : पहली बार नैनो डीएपी अपनाने लगे किसान

■ **कम लागत और बेहतर उत्पादन की उम्मीद**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेती अब परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसका ताजा उदाहरण एमसीबी जिले के ग्राम केल्हारी के किसान राय सिंह हैं, जिन्होंने इस खरीफ सीजन में पहली बार अपनी फसल के लिए नैनो डीएपी का उपयोग शुरू किया है। पिछले वर्ष गांव और आसपास के किसानों को मिले बेहतर परिणामों से प्रेरित होकर उन्होंने भी इस नई तकनीक को अपनाया है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में मिल रहा नैनो डीएपी

राय सिंह ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से नैनो डीएपी प्राप्त करते हुए बताया कि, खेती में नई तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता है। उनका कहना है कि यदि कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है तो किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष गांव के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था, जिससे उनकी फसलों की बढ़वार बेहतर रही और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इन्हीं सकारात्मक अनुभवों को देखकर उन्होंने इस वर्ष स्वयं भी इसका उपयोग करने का निर्णय लिया।

अब नहीं ढोनी पड़ती भारी बोरियां

राय सिंह के अनुसार पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं, जबकि नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर घर लाया जा सकता है। इससे समय, श्रम और परिवहन की परेशानी कम होती है। उन्होंने अन्य किसानों से भी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि वैज्ञानिक खेती ही भविष्य की जरूरत है और इससे खेती अधिक लाभकारी बनाई जा सकती है।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दे रहा है विभाग

कृषि विभाग भी किसानों को नैनो डीएपी के उपयोग, वैज्ञानिक खेती और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के संबंध में लगातार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दे रहा है।

छत्तीसगढ़ में मानसून की अच्छी बारिश खेती-किसानी के काम ने पकड़ी रफ्तार

■ **शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने चलाया ट्रैक्टर, धान रोपाई की कराई शुरुआत**

रायपुर। प्रदेश में मानसून की अच्छी वर्षा के साथ खेती-किसानी का कार्य गति पकड़ चुका है। इसी क्रम में दुर्ग शहर विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधि-विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव शुक्रवार को अपने गृहग्राम अहिवारा के समीप स्थित माटरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खेत में उतरकर कृषि कार्यों में सहभागिता निभाई।

मंत्री श्री यादव ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई से पूर्व खेत की मताई की तथा लगभग दो एकड़ भूमि को रोपाई के लिए तैयार कराया। इस दौरान उन्होंने खेत का निरीक्षण कर खाद की उपलब्धता एवं खेती की तैयारियों की जानकारी ली तथा किसानों को समय पर निंदाई-गुड़ाई सहित आवश्यक कृषि कार्य करने की सलाह दी। इसके पश्चात उन्होंने धान रोपाई कार्य का शुभारंभ कराया।

कृषि परंपरा और ग्रामीण संस्कृति के प्रति आत्मीय जुड़ाव

मंत्री बनने के बाद भी श्री यादव अपनी खेती की स्वयं देखरेख करते हैं तथा प्रतिवर्ष कृषि कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनका मानना है कि किसानों की मेहनत, चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए खेत से निरंतर जुड़े रहना आवश्यक है। किसान परिवार से होने के कारण वे किसानों की समस्याओं एवं जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। खेत में किसानों के साथ उनकी सक्रिय सहभागिता छत्तीसगढ़ की माटी, कृषि परंपरा और ग्रामीण संस्कृति के प्रति उनके आत्मीय जुड़ाव का सशक्त उदाहरण है।

खेती-किसानी हमारे जीवन का आधार

मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, उसे अपनी माटी, संस्कृति और मूल कार्य से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं किसान परिवार से हूं। खेती-किसानी हमारे जीवन का आधार है। समय मिलने पर आज भी खेत में जाकर खेती के कार्यों में भाग लेता हूं।" उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है।

छू लो आसमान के सफल विद्यार्थियों का वन मंत्री कश्यप ने किया सम्मान

■ नीट में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं, आगे की पढ़ाई में हरसंभव सहयोग का भरोसा

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने रविवार को छू लो आसमान आवासीय शैक्षणिक संस्थान, कारली में नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सफल विद्यार्थियों को गुलदस्ता, पुष्पमाला और टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

मेहनत, लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से मिली सफलता

वन मंत्री श्री कश्यप ने विद्यार्थियों की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि, यह उपलब्धि उनकी मेहनत, लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि आगे की पढ़ाई में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। शासन की ओर से उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने संस्था में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से नीट में सफल विद्यार्थियों से प्रेरणा लेने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी लगन एवं मेहनत से पढ़ाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत से कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।

'छू लो आसमान' योजना से विद्यार्थियों को मिल रहा बेहतर अवसर : दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित 'छू लो आसमान' पहल विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिल रहा है। कारली के विद्यार्थियों की नीट में सफलता इस बात का प्रमाण है कि उचित मार्गदर्शन, मेहनत और शासन की सुविधाओं से वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं।

पशु पालक रहें सावधान : बरसात में हरा चारा और पीने का पानी भी पशुओं को करते हैं बीमार

रायपुर। बरसात के मौसम में कदम-कदम पर पशुओं और साथ में पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संक्रमण वाली बीमारियां पशुओं को चपेट में लेना शुरू कर देती हैं। पशु बीमार होने के साथ ही तनाव में आ जाते हैं। इससे उत्पादन कम हो जाता है। पशु पालक की लागत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स की मानें तो, पशुओं को दिया जाने वाला हरा चारा और पीने का पानी भी बरसात के दिनों में पशुओं को बीमार कर सकता है। हरा चारा खि?लाने और पानी पिलाने में जरा सी चूक हुई नहीं कि पशु कई तरह की बीमारी की चपेट में आ जाता है।

जलभराव चारे को बनाता है प्रदूषित

क्योंकि बारिश के मौसम में खेत, बाग और जंगलों में चारों तरफहरा चारा खूब उगता है। जगह-जगह खुले मैदानों में पानी भर जाता है, और यही हरा चारा और खुले में भरा प्रदूषि?त पानी मॉनसून के मौसम में बीमारी की सबसे बड़ी जड़ बनते हैं। इसलिए इस मौसम में चारा खिलाने और पानी पिलाने के दौरान खासी सावधानियां बरतनी चाहिए।

पशुओं को न पिलाएं खुला पानी

विशेषज्ञों की मानें तो गांवों की पोखरों, तालाबों के साथ गड्ढों में पानी भर जाता है। लेकिन इसके साथ ही बरसात के इस पानी में कई तरह के कीटाणु पनपने लगते हैं। मच्छर भी जमा हुए पानी पर लार्वा छोड़ने लगते हैं, और जब हमारा पशु इस पानी को पीता है तो वो बीमार पड़ जाता है।

साफबर्तनों का करें इस्तेमाल

इसलिए खासतौर पर बरसात के दिनों में पशुओं को खुले में पानी न पिलाएं। हमेशा से ताजा पानी बाल्टी या किसी और बर्तन में लेकर ही पिलाएं। पानी घर पर ही पिलाएं. हो सके तो गांव के पोखर और तालाब में बारिश का पानी जमा न होने दें. अगर पानी जमा भी हो जाए तो उसमे लाल दवा मिला दें.

सहकारी चीनी मिलों के पुनर्जीवन के लिए 'एनसीडीसी' दे रही वित्तीय सहायता

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि, क्या केंद्र सरकार इस बात से अवगत है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं होने के बावजूद एक भी सहकारी चीनी मिल नहीं है। इस प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सहकारी चीनी मिल संचालित नहीं है। हालांकि, वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में आठ निजी चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिनमें से दो चीनी मिलें तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं।

केंद्र सरकार नहीं करती सहकारी चीनी मिलों की स्थापना - अमित शाह ने स्पष्ट किया कि, केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना नहीं करती है। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 अगस्त 1998 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चीनी उद्योग को अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस की सूची से हटा दिया गया था।

बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों के पुनर्जीवन के लिए उठाए कदम

उन्होंने कहा कि, सहकारिता मंत्रालय देश में बंद या कमजोर पड़ी सहकारी चीनी मिलों के पुनर्जीवन के लिए कई कदम उठा रहा है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम , जो सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक वैधानिक संस्था है, सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

ऐसे उपलब्ध कराई जाती है सहायता

यह सहायता या तो सीधे सहकारी चीनी मिलों को दी जाती है या फिर संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि, यह सहायता परियोजना की व्यवहार्यता , विस्तृत जांच-पड़ताल और एनसीडीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही स्वीकृत की जाती है।

पोल्ट्री संचालक दें ध्यान : बरसात में दाना ना हो नम, वरना बिगड़ सकती है मुर्गे-मुर्गियों की तबीयत

■ घर पर ऐसे बनाएं पोल्ट्री फीड, नहीं होगा खराब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी अब बड़ी संख्या में किसान पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। पोल्ट्री के मुर्गे-मुर्गियों के लिए रोजाना दाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि उन्हें फ्रेश फीड खि?लाया जाए। क्योंकि अगर फीड जरा सा भी खराब हुआ तो फिर उसका उत्पादन पर असर दिखाई देना तय है।

अनाज में नमी ना हो

ऐसे में यदि बरसात के दिनों में अगर फीड में नमी आ गई है तो फिर मुर्गियों की सेहत भी खराब हो सकती है। इसीलिए पोल्ट्री एक्सपर्ट खासतौर से बरसात के दिनों में घर पर ही पोल्ट्री फीड बनाने की सलाह देते हैं। खास ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कम संख्या में मुर्गे-मुर्गी होते हैं। क्योंकि ताजा फीड खि?लाने से उसमे नमी होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक्सपर्ट ये भी चेतावनी साफ शब्दों में देते हैं कि किसी भी हाल में फीड में इस्तेमाल होने वाले अनाज में नमी न हो।

अनाज को अच्छी तरह सुखाकर इस्तेमाल करें

अनाज को अच्छी तरह से सुखाकर ही फीड के लिए इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट की मानें तो पोल्ट्री सेक्टर एक ऐसा कारोबार है जहां करीब 70 फीसद लागत सिर्फ फीड यानि दाने पर आती है. अंडे-चिकन के रेट से लेकर पोल्ट्री फार्मर का मुनाफा क्या होगा ये भी फीड ही तय करता है. अंडा देने वाली मुर्गी हो या चिकन के लिए पाला गया मुर्गा, सभी को दिनभर में दो से तीन बार फीड चाहिए होता है।

फीड तैयार करते वक्त रखें ये ख्याल

प्री स्टार्टर फीड 400 ग्राम, स्टार्टर पोल्ट्री फीड 1200 ग्राम वजन का होने तक और फिनिशर फीड पोल्ट्री ब्रॉयलर मुर्गे के बिक जाने तक देना चाहिए।

- पोल्ट्री फार्म पर हर प्रकार का स्टॉक एडवांस में होना बहुत जरूरी है।
- पोल्ट्री फीड और फीड में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद सूखी जगह और धूप से दूर रखने चाहिये।
- पोल्ट्री फीड को मिलाने के लिये अच्छे मिक्सर की मदद लेनी चाहिये।
- पोल्ट्री फीड की पिसाई अच्छे से होनी चाहिये, क्योंकि फीड के मोटे दाने पचने में परेशान करते हैं।
- पोल्ट्री फीड सही से मिलाना चाहिये. पोल्ट्री फीड में सभी उत्पाद और तेल पहले अलग से कुछ फीड में मिला लेने चाहियें, फिर उसे सारे फीड में मिलाना चाहिये।
- पोल्ट्री फीड बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी सामान छूट ना जाये।
- पोल्ट्री फीड में डाले जाने वाले प्रत्येक उत्पाद की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें।
- प्रत्येक उत्पाद प्रतिष्ठित कंपनी का ही होना चाहिये।
- सोयाबीन की खली, मक्का और तेल खरीदने से पहले गुणवत्ता की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिये। सोयाबीन की खली और मक्का हर तरह के फंगस से मुक्त और सूखा होना चाहिये।
- मक्का में नमी 14 फीसद से कम और सोयाबीन की खली में लगभग 11 फीसद तक ही हो है।
- पोल्ट्री फार्म पर फीड इकट्ठा करने के दौरान ऐसी बोरियां इस्तेमाल न करें जो पहले दूसरे फार्म पर इस्तेमाल हो चुकी हों।
- फार्म पर फीड के लिए हमेशा नई बोरियां ही इस्तेमाल करें।

सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री कश्यप

रायपुर। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की 16 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उनके मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदेश के अंतिम किसान तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिजिटल बैंकिंग एवं आधुनिक तकनीक से सहकारिता व्यवस्था में किसानों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश: मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों को सक्रिय किया जाए। उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ हुए एमओयू के तहत कार्ययोजना बनाकर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

पैक्स का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण : बैठक में पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण एवं ऑडिट प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, ताकि सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बन सके।

किसानों को समय पर ऋण, खाद एवं बीज उपलब्ध कराने पर जोर : समीक्षा के दौरान बताया गया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से रू8,800 करोड़ कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 14 लाख से अधिक किसानों को रू 6,932 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 79 प्रतिशत है। मंत्री ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को समय पर उर्वरक, बीज एवं ब्याज अनुदान का लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार

मंत्री ने ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर एवं माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए।

गोदाम निर्माण एवं नवगठित पैक्स की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि RIDF योजना के अंतर्गत स्वीकृत 725 गोदामों में से 712 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष 13 गोदामों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन की भी समीक्षा की गई।

जन-शिकायतों एवं ई-ऑफिस पर सख्ती

मंत्री श्री कश्यप ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने तथा सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली एवं आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

धान उपार्जन का शीघ्र अंतिम निराकरण

बैठक में धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का पारदर्शी एवं शीघ्र अंतिम निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के अंत में मंत्री श्री केदार कश्यप ने सभी अधिकारियों से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए सहकारिता क्षेत्र और किसानों तक शासन की योजनाओं का त्वरित लाभ पहुँचाने का आह्वान किया।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री रमेश शर्मा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के. एन. कांडे, अपर पंजीयक श्री यू.बी.एस. राठिया, श्रीमती सावित्री भगत, सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के अनुरुप सहकारिता को नई गति दें : केदार कश्यप

■ बैंकों के रिक्त पदों पर भारतीय प्रक्रिया शुरु करने की मांग

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों एवं अपेक्स बैंक के अध्यक्षों ने आज मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप से सौजन्य भेंट कर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सहकारी संस्थाओं के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में अपेक्स बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष श्री सचिन सिंह बघेल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, सचिव सहकारिता श्री आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ श्री रमेश शर्मा तथा अपेक्स बैंक रायपुर के महाप्रबंधक श्री युगल किशोर वर्मा उपस्थित रहे।

'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा को गति देने पर जोर

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की ÷सहकार से समृद्धि÷ की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने पर बल दिया। उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा करते हुए पैक्स समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने तथा दुग्ध, मत्स्य, बुनकर एवं अन्य सहकारी समितियों के कार्य-व्यवसाय का विस्तार करने के निर्देश दिए।

डिजिटल सहकारिता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल

सचिव सहकारिता श्री आर. प्रसन्ना ने सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी कार्यप्रणाली, डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से सहकारी संस्थाएं अधिक सशक्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेंगी।

कंप्यूटरीकरण, मॉनिटरिंग एवं जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ श्री रमेश शर्मा ने सभी सहकारी समितियों के डिजिटल आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण को प्राथमिकता देने, नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए आपसी सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों, बेहतर विपणन व्यवस्था एवं वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ की पहल : बोर्ड के निर्णय के बाद जांजगीर में जिला सहकारी संघ गठन की प्रक्रिया शुरू

जांजगीर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ की स्थापना के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई है। राज्य सहकारी संघ के संचालक मंडल (बोर्ड) द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जिला सहकारी संघों के गठन के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रथम चरण के रूप में जांजगीर जिले में नवीन जिला सहकारी संघ के गठन की दिशा में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने जिले की सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जांजगीर जिले में जिला सहकारी संघ के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान करना तथा जिले की सहकारी संस्थाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना रहा।

बोर्ड के निर्णय से मिलेगा सहकारिता को नया विस्तार : सौरभ शर्मा

इस अवसर पर प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि राज्य सहकारी संघ के संचालक मंडल द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ स्थापित करने का निर्णय सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी संघों की स्थापना से जिले में कार्यरत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि जिला सहकारी संघ सहकारी संस्थाओं की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को राज्य स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। साथ ही प्रशिक्षण, सहकारी शिक्षा, सदस्यता विस्तार, जनजागरूकता, क्षमता विकास एवं सहकारी गतिविधियों के प्रभावी संचालन को भी नई गति मिलेगी।

प्रस्तुत किए गए सुझाव और विचार-

बैठक में सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जिला सहकारी संघ के गठन के संबंध में अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए गए। नवीन जिला सहकारी संघ के गठन की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। राज्य संघ द्वारा प्रथम चरण में जांजगीर जिले से प्रारंभ की गई यह पहल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को संगठित, सशक्त एवं व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इनकी रही मौजूदगी- इस अवसर पर सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम शर्मा, विभिन्न समितियों प्राधिकृत अधिकारी प्रमोद कुमार देवांगन, मणिकांत अग्रवाल, पुष्पेन्द्र कुमार थवाईत, संजय कुमार राठौर, गौरशंकर साहू, चेतन दास महंत, हीरासाय साहू, रामभरोस सूर्यवंशी, ओमप्रकाश यादव, नर्मदा प्रसाद जायसवाल, धन्नू डडसेना, बाला जी सिंह सिसोदिया, उमेश कुमार राठौर एवं प्रमोद कुमार कश्यप आदि उपस्थित थे।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक विवेकानंद झा द्वारा क्वालिटी आफसेट, पुरानी बस्ती, रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail : cgcoopnews@gmail.com